ONOE

BPSC करेंट अफेयर्स

By SK Choudhary Sir

Topic:

- एक देश, एक चुनाव: लाभ, चुनौतियाँ और आगे की राह

एक देश, एक चुनाव: लाभ, चुनौतियाँ और आगे की राह

- वर्तमान संदर्भ
- एक देश, एक चुनाव क्या है?
- एक देश एक चुनाव ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- महत्त्व/पक्ष मे तर्क
- एक देश एक चुनाव प्रमुख चुनौतीयां -
- भविष्य या आगे की राह
- निष्कर्ष

वर्तमान संदर्भ

→ 1 सितम्बर, 2023

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कि अध्यक्षता मे 'एक देश, एक चुनाव' पर अध्ययन के लिए समिति कि स्थापना की हुई।

एक देश, एक चुनाव क्या है?

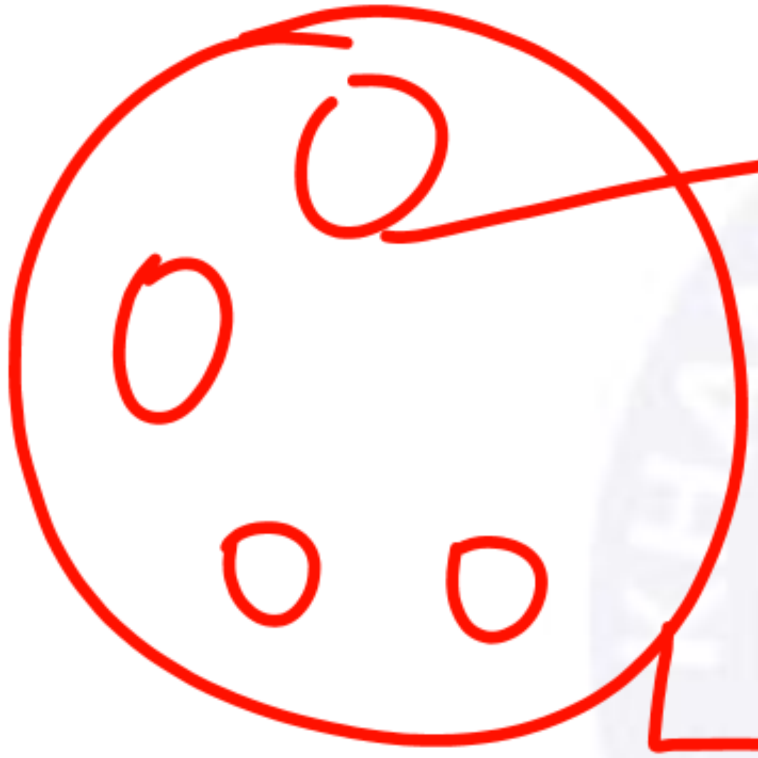

→ 28 राज्य + 2 UT's ⇒ विधानसभा

→ भारत → लोकसभा

एकीकृत चुनाव की प्रक्रिया

एक देश, एक चुनाव ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आज़ादी के बाद एक देश, एक चुनाव : 1952, 1957, 1962, 1967 } लोकसभा + विधानसभा

↑ अलग-अलग चुनाव LS VS

2019 लोकसभा

↑

(2024) ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश

महत्त्व/पक्ष मे तर्क

1. विभिन्न समिति आयोग की सिफारिश
2. राज्यों के वित्तीय बोझ में कमी
3. फ्री- बीज में कमी
4. सुरक्षा बलों तथा लॉजिस्टिक जरूरत में कटौती आदर्श
5. आचार संहिता की अवधि में कमी
6. प्रशासनिक दक्षता में सुधार चुनावी लगता में कमी
7. मतदान का प्रतिशत दर में वृद्धि

2019 → LS
60,000 करोड़
EVM/VVPAT
30%
VS
60%
40%

Khan Global Studies

By : SKC Sir

"आदर्श आचार संहिता"

LS

VS

EC

2 Months

① विभिन्न समितियों/आयोगों की सिफारिशें :-

→ 1983 में "निर्वाचन आयोग" द्वारा

→ 1999 में 170वें विधि आयोग के अध्यक्ष बी० पी० संजीव रेड्डी

→ 2015 में संसदीय समिति द्वारा → ई० एम० सुदर्शन अध्यक्ष

एक देश, एक चुनाव की सिफारिश की गई थी।

एक देश, एक चुनाव प्रमुख चुनौतीयां -

1. संघात्मक ढांचे पर प्रहार
2. वृहत स्तर पर संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता
3. राज्यों की विधानसभा तथा लोकसभा के कार्यकाल का समन्वय स्थापित करना
4. लॉजिस्टिक संबंधित चुनौती
5. लागत प्रभावी नहीं होने के आशंका
6. चुनावी खरीद फरोख्त की घटनाओं में वृद्धि की संभावना

अनु॰- 83 → संसदीय विधायिका के कार्यकाल

" 85 → राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने शक्ति

" 172 → राज्य विधानमंडल का कार्यकाल

" 174 → राज्य की विधानसभा भंग करने की शक्ति

" 356 → राज्यों 'संवैधानिक आपातकाल' 'राष्ट्रपति शासन'

⇒

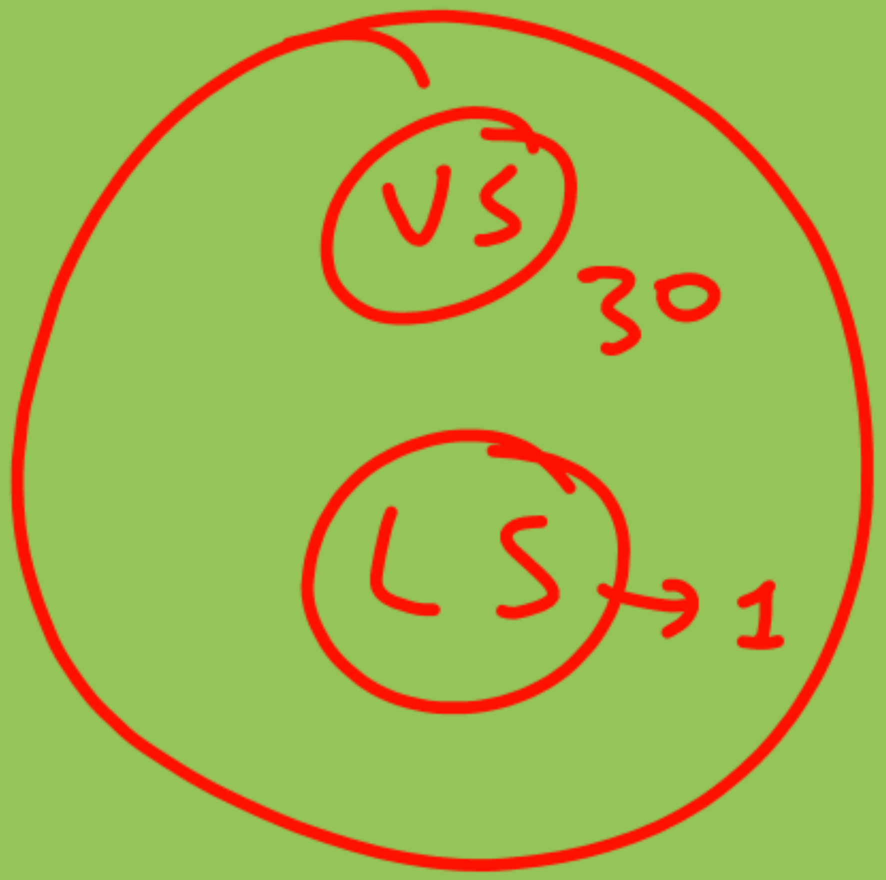

राज्य विशेष का मुद्दा

देश " " "

भविष्य या आगे की राह

1. व्यापक संवैधानिक समीक्षा की आवश्यकता
2. संघवाद एवं केंद्रीयकरण में संतुलन
3. हाइब्रिड जवाबदेही मॉडल
4. चुनावी लागत लाभ पारदर्शी विश्लेषण
5. पायलट मोड द्वारा प्रयोग

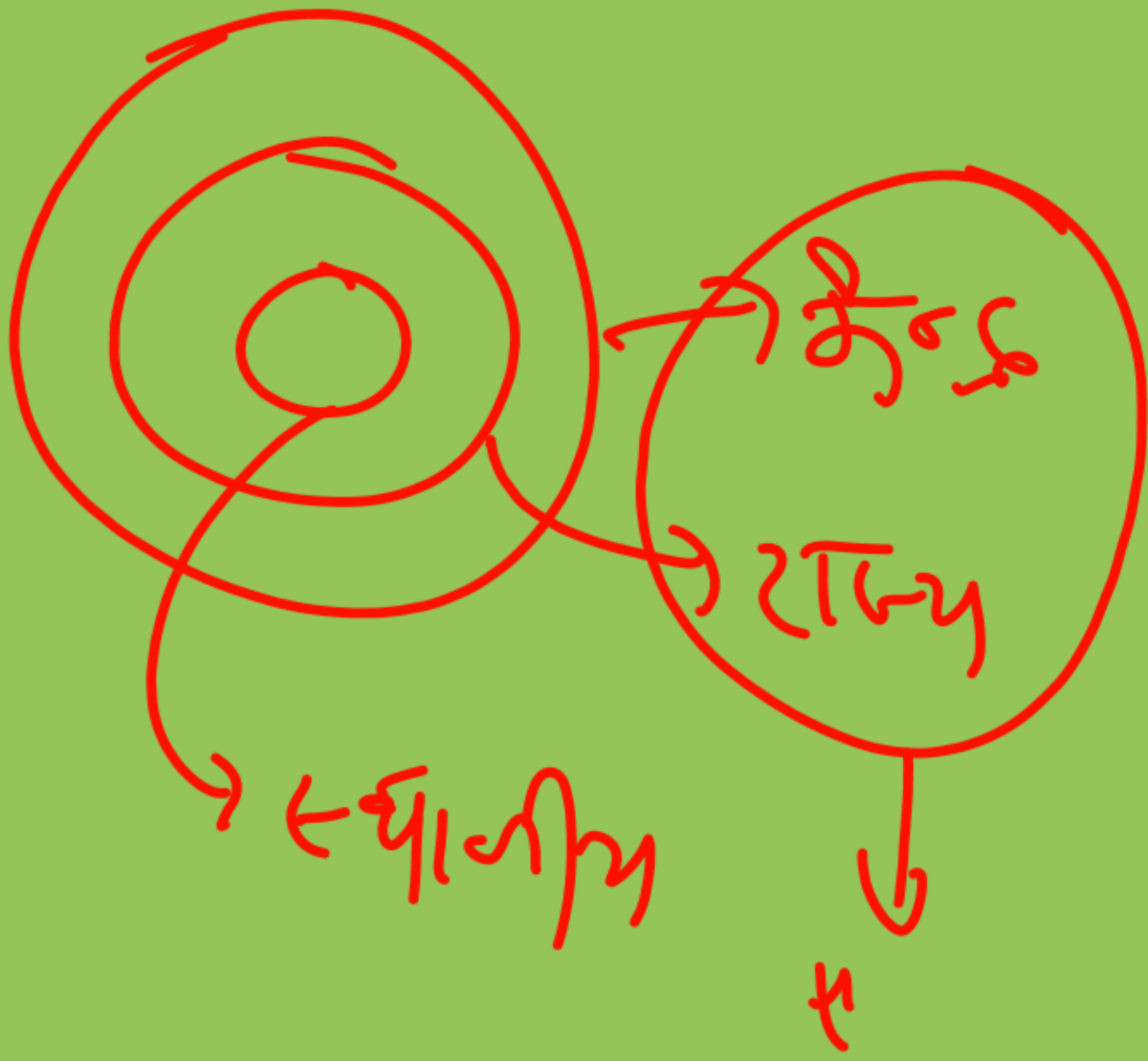
কেন্দ্র
রাজ্য
স্থানীয়

निष्कर्ष

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

Q.01. "लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी।" चर्चा कीजिये।

Q.02. 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा का विश्लेषण कीजिये और इससे जुड़े लाभों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इसे व्यवहार्य बनाने के लिये कुछ उपाय भी सुझाइये।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

Q.01. हाल ही भारतीय संसद ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम - 2023" को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक का मूल्यांकन करते हुए। इसके महत्व और चुनौतियां की स्पष्ट व्याख्या करें।

Recently, the Indian Parliament has taken a historic step and given final approval to "Nari Shakti Vandan Act – 2023". While evaluating this bill. Explain clearly its importance and challenges.

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

Q.02. हाल ही में खबरों में रहा "नारी शक्ति वंदन अधिनियम - 2023" की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करें। इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क से स्पष्ट करें कि यह किस प्रकार महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है?

Discuss the need and importance of "Nari Shakti Vandan Act – 2023" which was in the news recently. Explain with your arguments in favor and against how it can play an important role in the empowerment of women?

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

Q.03. क्या चर्चित “नारी शक्ति वंदन अधिनियम - 2023” महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक था? क्या इससे महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो पाएगा? अपना पक्ष रखें।

Was the much talked about “Nari Shakti Vandan Act – 2023” necessary for women empowerment? Will this ensure women empowerment? make your point.

Thank you
By SK Choudhary Sir

Topic: Short Notes

1. यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश
2. AUKUS समझौता
3. वनवेब इंडिया-2 मिशन
4. ग्रेट निकोबार परियोजना

CA

GS-I, Section-II

GS-II

BPSC Mains करेंट अफेयर्स

GS, Paper -1, Section -02

Khan Global Studies

By : SKC Sir

'यूरोपीय'

UK

≠

CPTPP

10 देशों

+1

11

FTA

'मुक्त व्यापार समझौता'

UAE

Australia

India

UK 2030

यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल

- संदर्भ
- Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
- मुख्य बिंदु

THE CPTPP MARKETS
11 COUNTRIES
500 MILLION CONSUMERS
$13.5 TRILLION IN GDP
UK

❑ मुख्य बिंदु

- यूनाइटेड किंगडम (यूके) औपचारिक रूप से 16 जुलाई, 2023 को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। सीपीटीपीपी कनाडा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 10 अन्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। अन्य देश हैं:
- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम।
- सीपीटीपीपी में यूके का शामिल होना 2024 की दूसरी छमाही में प्रभावी होने की उम्मीद है।

- सीपीटीपीपी में यूके के शामिल होने का उद्देश्य है:
- देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
- 500 मिलियन से अधिक लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करना
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना
- अधिक आर्थिक लचीलेपन का समर्थन करना
- ब्रिटिश व्यवसायों को पूरे क्षेत्र में अधिक स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देना

AUKUS समझौता

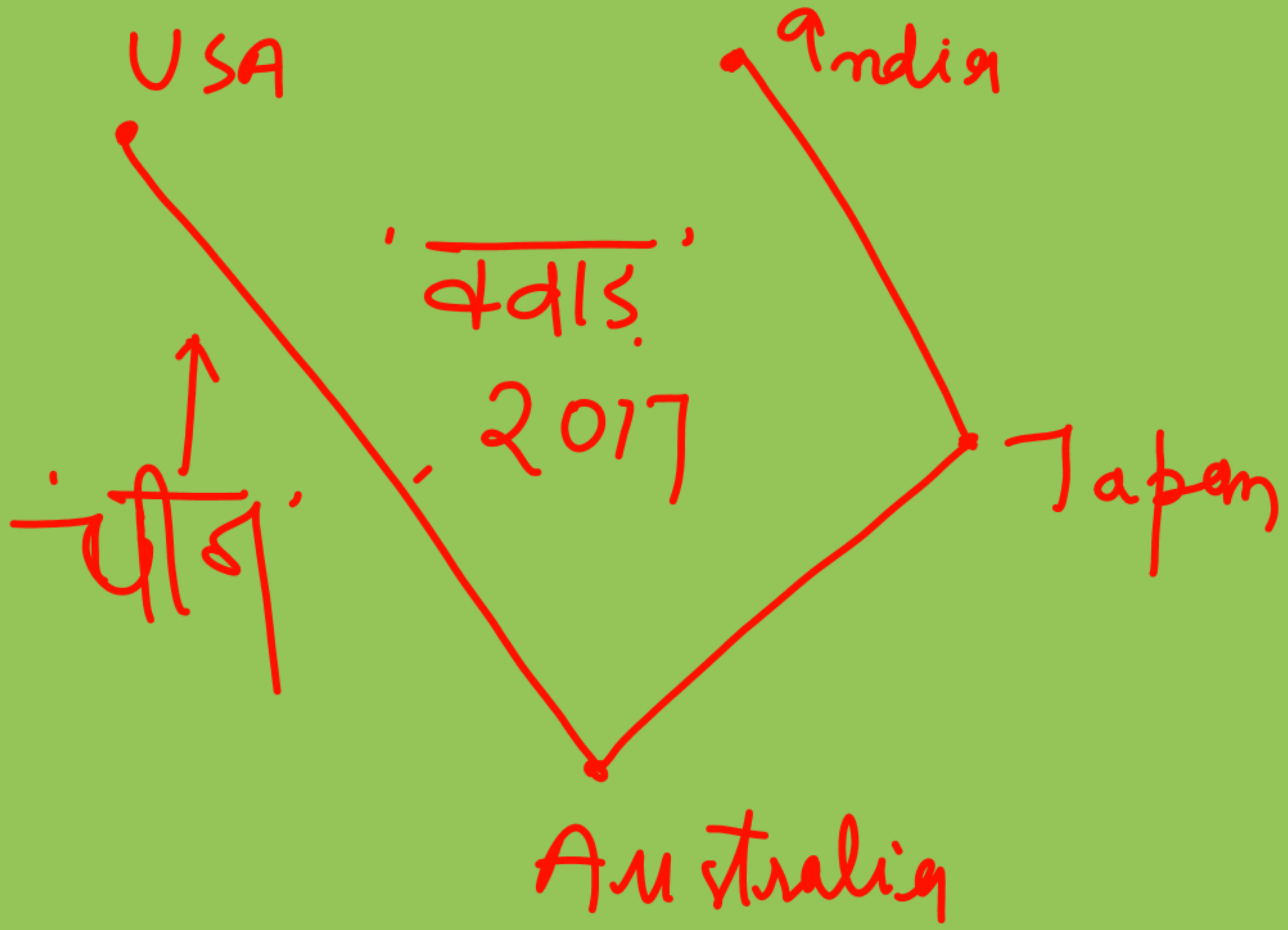
USA
India
'क्वाड'
2017
'चीन'
Japan
Australia

❑ मुख्य बिंदु

- AUKUS की स्थापना- 15 सितंबर, 2021
- ऑकस एक उन्नत त्रिपक्षीय, रणनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है. यह गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच है.
- इस गठबंधन का उद्देश्य सुरक्षा और रक्षा हितों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक सरकार की क्षमता को मज़बूत करना है.
- ऑकस के तहत, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेंगे. यह

- ऑकस के नेताओं ने 13 मार्च, 2023 को घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक रूप से सशस्त्र, परमाणु-संचालित पनडुब्बियों (एसएसएन) हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए इष्टतम मार्ग के तहत है, 2027 के बाद, बारी-बारी से यूके की एक एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बी और अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की 4 पनडुब्बियां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के नज़दीक HMAS स्टर्लिंग बेस पर तैनात होंगी.
-

वनवेब इंडिया-2 मिशन

- संदर्भ
- मुख्य बिंदु

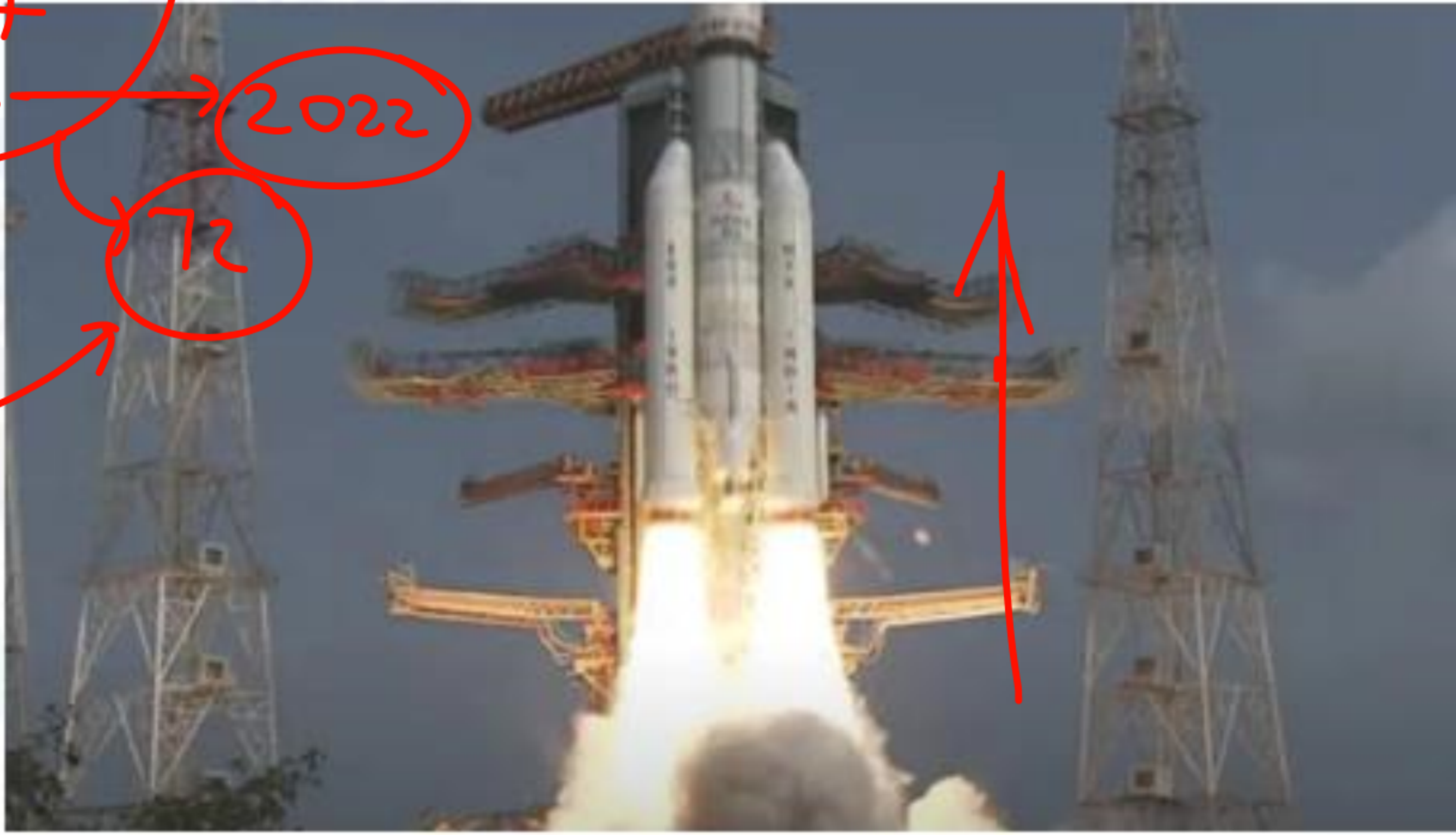

❑ मुख्य बिंदु

- वनवेब इंडिया-2 मिशन के तहत, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 26 मार्च, 2023 को ब्रिटेन के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया. इन उपग्रहों का कुल वज़न 5,805 किलोग्राम था. इस मिशन को LVM3-M3/वनवेब इंडिया-2 नाम दिया गया था.

- इसरो ने अपनी सबसे भारी रॉकेट, एलवीएम3 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष पोर्ट से लॉन्च किया. यह रॉकेट छठी बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था. इस रॉकेट ने वनवेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 87.4 डिग्री के झुकाव के

- वनवेब एक यूके आधारित कंपनी है. यह एक वैश्विक संचार नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट प्रदान करना है. यह सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है.

- ISRO की वाणिज्यिक शाखा NSIL ने वनवेब के साथ 72 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे. 23 अक्टूबर, 2022 को LVM3-M2/वनवेब इंडिया-1 मिशन में 36 उपग्रहों का पहला समूह लॉन्च

ग्रेट निकोबार परियोजना

- संदर्भ
- मुख्य बिंदु

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के निर्माण को लेकर पर्यावरणीय चिंता प्रकट की जा रही है।

72° E
ISLANDS
LOW - HILLS
Saddle Peak
North Andaman
Andaman Islands
Middle Andaman
Andaman Sea
Lower Andaman
Port Blair
Sentinel Island
11° N
Bay of Bengal
Little Andaman
Andaman and Nicobar Islands
100 mi
100 km
Car Nicobar
Indian Ocean
Nicobar Islands
Bompoka
Teressa
Nancowry
Katchall
Little Nicobar
Great Nicobar
NGT

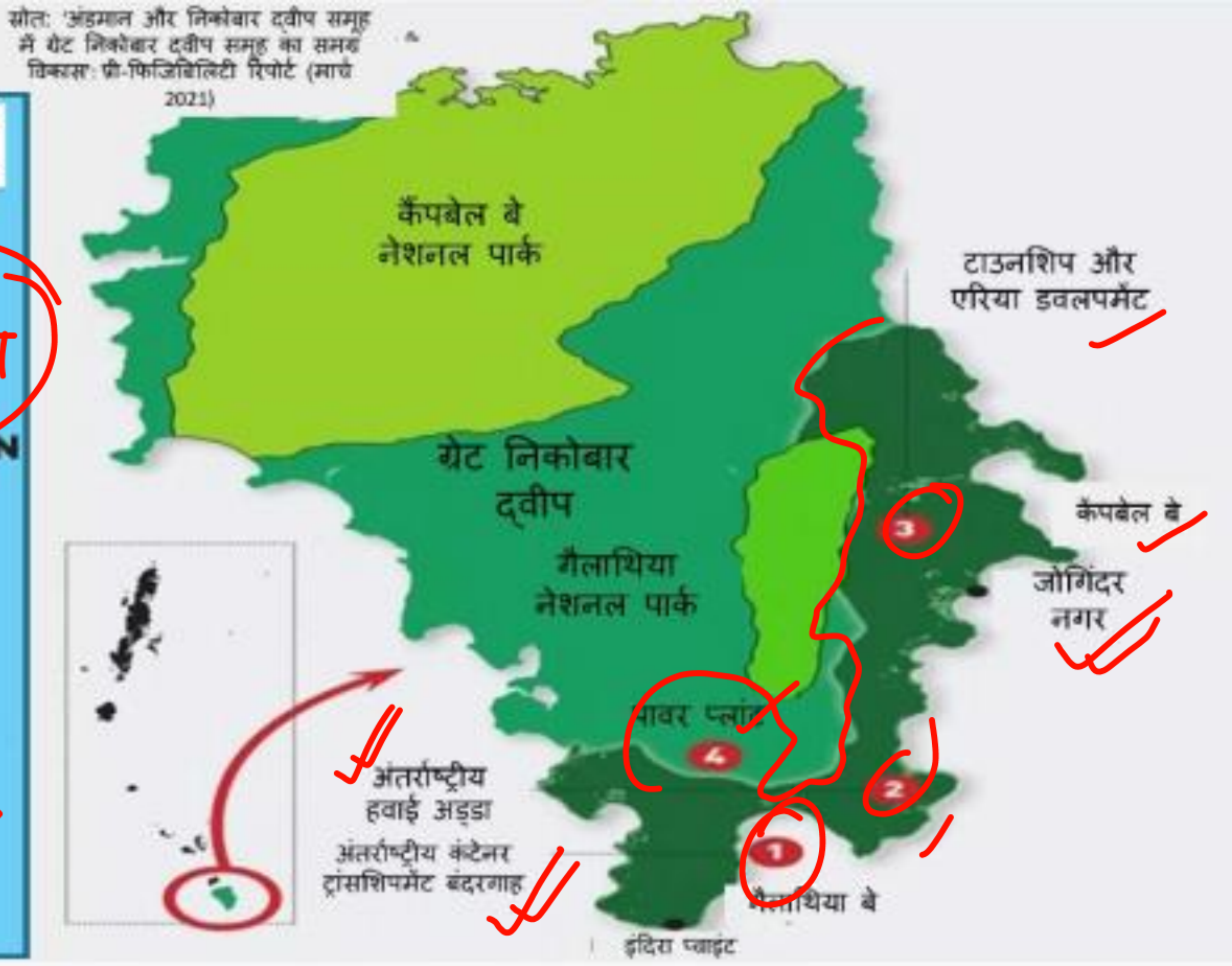
स्रोत: 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास: प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (मार्च 2021)
कैंपबेल बे नेशनल पार्क
टाउनशिप और एरिया डवलपमेंट
ग्रेट निकोबार द्वीप
गैलाथिया नेशनल पार्क
कैंपबेल बे
जोगिंदर नगर
पावर प्लांट
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह
गैलाथिया बे
इंदिरा प्वाइंट

❑ मुख्य बिंदु

- जनवरी 2023 में संवैधानिक आचरण समूह जिसमें लगभग 100 पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे , ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की थी।
- परियोजना का संचालन - नीति आयोग
- नोडल एजेंसी - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)
- इस परियोजना पर होने वाला अनुमानित व्यय लगभग 72,000 करोड़ रुपए है।

उद्देश्य

- ग्रेट निकोबार विकास योजना भारत के अंडमान सागर में ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे के लिए एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना है। शामिल हैं:

1. एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईटीपी)
2. एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
3. एक बिजली संयंत्र
4. एक नई टाउनशिप जो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का गठन

निकोबार परियोजना से जुड़ी चिंताएं

- इस परियोजना के लिए प्राचीन वर्षावनों में लाखों पेड़ काटे जाएंगे तथा लगभग 12 से 20 हेक्टेयर मैंग्रोव कवर का विनाश होगा।
- लगभग 10 हेक्टेयर प्रवाल आवरण प्रभावित हो सकते हैं।
- स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजाति के मूल निवासी प्रभावित होंगे।
- दुर्लभ जीव भी इस परियोजना से प्रभावित होंगे।

उद्देश्य

- ग्रेटर निकोबार के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
- इस परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र तथा एक टाउनशिप कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है।
- इसके अलावा, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में एक लाख पेड़ों को काटकर बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

Thank you
By SK Choudhary Sir